



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 2 अक्टूबर, 2021 ई० (आश्विन 10, 1943 शक संवत्) [संख्या 40

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	725—739	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1381—1409	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	741—747	975
			स्टोसे—पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

17 अगस्त, 2021 ई0

सं0 4027/77-4-21-71एन/21-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रबन्धक (सिविल) के पद पर कार्यरत स्व0 नवाब सिंह की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1642, दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री निशांत कुमार सिंह पुत्र स्व0 नवाब सिंह की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री निशांत कुमार सिंह को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री निशांत कुमार सिंह द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री निशांत कुमार सिंह द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।
- (3) श्री निशांत कुमार सिंह द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री निशांत कुमार सिंह की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4029/77-4-21-69एन/21-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अनुरक्षक के पद पर कार्यरत स्व0 बाबूराम की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1665, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती

नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री भीम प्रसाद यादव पुत्र स्व० बाबूराम की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु० 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु० 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री भीम प्रसाद यादव को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री भीम प्रसाद यादव द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री भीम प्रसाद यादव द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।
- (3) श्री भीम प्रसाद यादव द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी०सी०सी० प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री भीम प्रसाद यादव की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं० 4490/77-4-21-47जीएन/21—ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्यरत स्व० मदन गोपाल की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक ग्रैनौ/कार्मिक/एच-145/2021/531, दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री सुशांत कुमार पुत्र स्व० मदन गोपाल की मृतक आश्रित के रूप में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु० 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु० 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री सुशांत कुमार को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री सुशांत कुमार द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व थे। यदि श्री सुशांत कुमार द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

- (3) श्री सुशांत कुमार द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री सुशांत कुमार की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4491/77-4-21-44जीएन/21—ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत स्व0 नन्दन प्रसाद आर्या की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक ग्रेनौ/कार्मिक/एच-145/2021/533, दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री अक्षय कुमार पुत्र स्व0 नन्दन प्रसाद आर्या की मृतक आश्रित के रूप में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री अक्षय कुमार को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री अक्षय कुमार द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री अक्षय कुमार द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।
- (3) श्री अक्षय कुमार द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री अक्षय कुमार की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4492/77-4-21-45जीएन/21—ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत स्व0 समरजीत की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक ग्रेनौ/कार्मिक/एच-155/2021/532, दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री इन्द्र जीत यादव पुत्र स्व0 समरजीत की मृतक आश्रित के रूप में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री इन्द्र जीत यादव को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री इन्द्र जीत यादव द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री इन्द्र जीत यादव द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) श्री इन्द्र जीत यादव द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री इन्द्र जीत यादव की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4505/77-4-21-68एन/21—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अनुरक्षक के पद पर कार्यरत स्व0 विजय प्रकाश की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1663, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्रीमती रीता पत्नी स्व0 विजय प्रकाश की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्रीमती रीता को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्रीमती रीता द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्रीमती रीता द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

- (3) श्रीमती रीता द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्रीमती रीता की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4508/77-4-21-2748/19—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रबंधक (सिविल) के पद पर कार्यरत स्व0 गंगा दयाल की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1666, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री अभिजीत दयाल पुत्र स्व0 गंगा दयाल की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री अभिजीत दयाल को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री अभिजीत दयाल द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री अभिजीत दयाल द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।
- (3) श्री अभिजीत दयाल द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री अभिजीत दयाल की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4509/77-4-21-72एन/21-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उद्यानकर्मी के पद पर कार्यरत स्व0 जगन सिंह की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1664, दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्रीमती प्रवीन सिंह पत्नी स्व0 जगन सिंह की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्रीमती प्रवीन सिंह को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्रीमती प्रवीन सिंह द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्रीमती प्रवीन सिंह द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) श्रीमती प्रवीन सिंह द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्रीमती प्रवीन सिंह की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

सं0 4510/77-4-21-80एन/21-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उद्यानकर्मी के पद पर कार्यरत स्व0 स्नेहलता की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1643, दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री अमित शर्मा पुत्र स्व0 स्नेहलता की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री अमित शर्मा को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री अमित शर्मा द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक

पूर्व आश्रित थे। यदि श्री अमित शर्मा द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

- (3) श्री अमित शर्मा द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री अमित शर्मा की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2-उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

19 अगस्त, 2021 ई0

सं0 4180/77-4-21-82एन/21-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सहायक मैकेनिक कम ऑपरेटर के पद पर कार्यरत स्व0 करनराम की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1641, दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्रीमती कविता पत्नी स्व0 करनराम की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्रीमती कविता को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्रीमती कविता द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्रीमती कविता द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) श्रीमती कविता द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्रीमती कविता की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

24 अगस्त, 2021 ई0

सं0 4028/77-4-21-70एन/21—नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रबन्धक सिविल के पद पर कार्यरत स्व0 राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नोएडा/कार्मिक/2021/1644, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री विशाल कीर्ति पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद की मृतक आश्रित के रूप में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

- (1) श्री विशाल कीर्ति को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
- (2) श्री विशाल कीर्ति द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री विशाल कीर्ति द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) श्री विशाल कीर्ति द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
- (4) श्री विशाल कीर्ति की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

26 जुलाई, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-835/11-2021-06/2021—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों (संयुक्त आयुक्त) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद

पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, वाणिज्य कर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1403	श्री राजाराम गुप्ता
2	1404	श्री जय प्रकाश नारायण पटेल
3	1406	श्री सुबास चन्द्र-II
4	1408	श्री नन्हू लाल सोनी

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य योजना आयोग-2

(नियोजन विभाग)

प्रोन्नति

02 अगस्त, 2021 ई0

सं० (1211/21) 1/9/35-आ०-2/2014-17—श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग में कार्यरत श्री अरविन्द कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अपर निदेशक के पद पे-मैट्रिक्स लेवल-13 रु० 1,23,100-2,15,900 पर पदोन्नति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री अरविन्द कुमार वर्मा को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

सं० (1212/21) 1/16/35-आ०-2/2014-29—विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य योजना आयोग के निम्नलिखित शोध अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-11 रु० 67,700-2,08,700 में नियमित रूप से पदोन्नत किया जाता है :

- 1—श्री अवधेश कुमार निगम
- 2—श्री शिशिर श्रीवास्तव
- 3—श्री गंगाधर कुशवाहा
- 4—श्री बृज भूषण
- 5—श्री आनन्द प्रकाश
- 6—डा० राजश्री चौधरी
- 7—श्री लाल बहादुर यादव

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

कार्मिक विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

24 अगस्त, 2021 ई0

सं० 15/39/2000-टी०सी०-2-का-4-2021—‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल महोदया, श्री प्रेमनाथ, सी-13, एन०एफ०एल सोसाइटी, सेक्टर पाई-2

ग्रेटर नोयडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0-201310 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के रिक्त पद पर सहर्ष नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

17 अगस्त, 2021 ई0

सं0 89551/71-1001(001)/12/2021(जी-103/2018)—उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, सामान्य सर्जरी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 19(V)/11/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 00 जुलाई, 2021 एवं संख्या 19(IV)/11/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 23 जून, 2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 04 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

सूची

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि0 नं0/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहां तैनाती की गयी है
1	डा0 पंकज कुमार कनौजिया पुत्र श्री सतीश चन्द्र कनौजिया, (रजिस्ट्रेशन नं0 53200033244) अना0/अनु0 जाति	ए-1, नई गंज, जौनपुर, उ0प्र0-222002	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
2	डा0 सुधांशु शर्मा पुत्र श्री सुनील दत्त शर्मा, (रजिस्ट्रेशन नं0 53200007683) अना0/ओ0बी0सी0	पुष्पेय हास्पिटल, गांधी नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0-209101	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
3	डा0 सुबोध कुमार सिंह पुत्र श्री छत्तर सिंह, (रजिस्ट्रेशन नं0 53200027349) अनु0 जाति	बी/बी-14, चन्दनवन फेज-1, मथुरा (उ0प्र0), पिन-281001	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
4	डा0 गौरव मिश्रा पुत्र श्री आनन्द कुमार मिश्रा, (रजिस्ट्रेशन नं0 53200008293) अनारक्षित	ए-58, जलवायु विहार कालोनी, फेज-2, मानसरोवर योजना सेक्टर एल, एल0डी0ए0 लखनऊ (उ0प्र0), पिन-226012	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

- (2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।
- (4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निर्बन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे—

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3—जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4—अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5—जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

नामकरण

10 अगस्त, 2021 ई0

सं0 सा0-1253/23-1-2021-242सा/21—जनपद प्रयागराज के 02 मार्गों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 604/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20,

दिनांक 20 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्या 776/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :

क्र०	जनपद	वर्तमान में मार्ग	नामकरण
1	2	3	4
1	प्रयागराज	मऊआइमा से धीनपुर मार्ग (अ०जि०मा०), लं०-12.60 कि०मी०	रंगबहादुर पटेल मार्ग
2	प्रयागराज	सोरांव होलागढ़ मार्ग (अ०जि०मा०), लं०-13.25 कि०मी०	दीनानाथ शुक्ल मार्ग

13 अगस्त, 2021 ई०

सं० सा०-1537/23-1-2021-171सा/19 टीसी-जनपद आगरा एवं गौतमबुद्धनगर के 02 मार्गों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 802/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 27 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 803/02 आई०डी०एस० प्रकोष्ठ/20, दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :

क्र०	जनपद	वर्तमान में मार्ग	नामकरण
1	2	3	4
1	आगरा	ए०बी०के० से लालपुरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग), लम्बाई-1.10 कि०मी०	“शहीद निर्वेश कुमार मार्ग”
2	गौतमबुद्धनगर	छपरौला दुजाना आकिलपुर प्यावली एन०टी०पी०सी० मार्ग (अ०जि०मा०), लम्बाई-17.450 कि०मी०	“शहीद ज्ञानचन्द मार्ग”

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-4

प्रोन्नति

19 अगस्त, 2021 ई०

सं० 920/23-4-2021-55 एनजी/2017-सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) की पदोन्नति श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 762/04/पी/सेवा-6/2020-21, दिनांक 16 जुलाई, 2021 द्वारा प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक को सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2, रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 (पुनरीक्षित पे-बैण्ड-3 के लेवल-10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नति करते हुये 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अवर अभियन्ता (विद्युत)/(यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक)

क्रमांक	नाम
1	2
1	श्री राम औतार, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), ज्येष्ठता क्रमांक-467
2	श्री तरणी प्रसाद चौरसिया, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), ज्येष्ठता क्रमांक-471ए
3	श्री ओम तत्सत लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), ज्येष्ठता क्रमांक-471बी

1	2
4	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियंता (याँत्रिक), ज्येष्ठता क्रमांक-471एफ
5	श्री चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, अवर अभियंता (याँत्रिक), ज्येष्ठता क्रमांक-484
6	श्री जय प्रकाश, अवर अभियंता (विद्युत), ज्येष्ठता क्रमांक-419
7	श्री महेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियंता (विद्युत), ज्येष्ठता क्रमांक-432
8	श्री कैलाश नाथ पाल, अवर अभियंता (विद्युत), ज्येष्ठता क्रमांक-433

2—उक्त अभियन्तागण अग्रिम आदेशों तक अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये यथावत कार्य करते रहेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे तथा इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
समीर वर्मा,
सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

13 अगस्त, 2021 ई0

सं0 1081/22-1-2021-107/99—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैंड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, ग्रेड-1 को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार, ग्रेड-2, वेतन बैंड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदया एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0सं0	नाम
1	श्री विनोद कुमार सिंह
2	श्री प्रेमनाथ पाण्डेय
3	श्री रामधनी
4	श्री राधाकृष्ण मिश्र

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

भाषा विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

12 अगस्त, 2021 ई0

सं0 236/इक्कीस-1-2021-1(2)/96—उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी के उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किये जाने विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या 104/इक्कीस-1-2020-1(2)/96—टी0सी0-II, दिनांक

23 जुलाई, 2020 के क्रम में अधोवर्णित महानुभावों को उनके नाम के समक्ष अंकित पदनाम के अनुसार उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ में पुनः एक वर्ष के लिये एतद्द्वारा नामित किया जाता है—

क्रमांक	पदधारियों का नाम एवं पता	पदनाम
1	श्री नानक चन्द लखमानी, लखनऊ	उपाध्यक्ष
2	श्री माधव लखमानी, लखनऊ	सदस्य
3	श्री नरेश कुमार बजाज, गोरखपुर	सदस्य
4	श्री ज्ञान प्रकाश टेकचन्दानी, अयोध्या	सदस्य
5	श्री विजय कुमार पुर्सवानी, इलाहाबाद	सदस्य
6	श्री लालू गंगवानी, कानपुर	सदस्य
7	श्री हेमंत भोजवानी, आगरा	सदस्य
8	श्री लीलाराम सचदेवा, वाराणसी	सदस्य

2—उपर्युक्त नामित पदधारियों को वित्त (सामान्य), अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार यथा प्रावधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

3—उपर्युक्त नामांकन को राज्य सरकार द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

सं0 243/इक्कीस-1-2021-5(3)/94—उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 9(1)(4) एवं नियम 9(1) (6 से 10) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को उनके नामांकन के दिनांक से एक वर्ष के लिये उनके नामों के सम्मुख यथोल्लिखित रूप से उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ में नामित किया जाता है—

क्रमांक	पदधारियों का नाम एवं पता	पदनाम
1	श्री गुरबिन्दर सिंह छाबड़ा (विकी), कानपुर	उपाध्यक्ष
2	श्री जसविन्दर सिंह, जौनपुर	सदस्य
3	श्री रामकुमार छाबड़ा, मुजफ्फरनगर	सदस्य
4	श्री सुखदर्शन बेदी, मुजफ्फरनगर	सदस्य
5	श्री लखविन्दर पाल सिंह, लखनऊ	सदस्य
6	श्री जगजैन सिंह 'नीटू', गोरखपुर	सदस्य

2—उपर्युक्त नामित पदधारियों को वित्त (सामान्य), अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार यथा प्रावधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

3—उपर्युक्त नामांकन को राज्य सरकार द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २ अक्टूबर, २०२१ ई० (आश्विन १०, १९४३ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION NOTIFICATION

July 28, 2021

Correction Slip No. 268

No. 472/VIIIc, Allahabad.—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I and II, with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

The Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2021

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these Rules, unless the context otherwise requires, “Rules” mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

3. Amendment of Rule 9 of Chapter IV.—Sub-rule (1) of Rule 9 of Chapter IV of the Rules shall be amended as follows :

Existing Provision

9. Full particulars of persons and places to be given.—(1) An affidavit, shall fully describe the person swearing it with such particulars as will ensure his clear identification such as his full name, his age, the name of his father, **his religious persuasion,**

Amendment

9. Full particulars of persons and places to be given.—(1) An affidavit, shall fully describe the person swearing it with such particulars as will ensure his clear identification such as his full name, his age, the name of his father, his rank or

Existing Provision

his rank or degree in life, his profession, calling, occupation or trade and his true place of residence. Any person or place referred to in an affidavit shall be fully described in such manner as to enable his or its identity to be clearly fixed. In addition to the full description of the person swearing the affidavit, the deponent will annex his/her passport size photograph alongwith the proof of his identity such as, driving licence, ration card, Kisan Bahi, identity card issued by Election Commission of India, passbook of any nationalized bank, passport, arms licence, PAN card issued by the Income-Tax Department, identity card issued by the Bar Council or other organisation or authority of which the person identifying belongs; or any other documentary identity proof recognised by the Election Commission of India for casting vote in the Parliamentary or Assembly Elections.

Amendment

degree in life, his profession, calling, occupation or trade and his true place of residence. Any person or place referred to in an affidavit shall be fully described in such manner as to enable his or its identity to be clearly fixed. In addition to the full description of the person swearing the affidavit, the deponent will annex his/her passport size photograph alongwith the proof of his identity such as, driving licence, ration card, Kisan Bahi, identity card issued by Election Commission of India, passbook of any nationalized bank, passport, arms licence, PAN card issued by the Income-Tax Department, identity card issued by the Bar Council or other organisation or authority of which the person identifying belongs; or any other documentary identity proof recognised by the Election Commission of India for casting vote in the Parliamentary or Assembly Elections.

4. Amendment of Chapter XXIII.—Chapter XXIII of the Rules shall be substituted as follows:**Existing Provision****CHAPTER XXIII****Section 'A'—Cases other than Criminal Cases**

1. Title of petition:—A petition for certificate of fitness to appeal to the Supreme Court of India shall be entitled :

In the High Court of Judicature at Allahabad.
Petition for Certificate

Under Article() of the Constitution of India.

Supreme Court Petition No.....of.....

2. Contents of petition:—The petition shall contain a brief statement of the case and the grounds of appeal.

Amendment**CHAPTER XXIII****Section 'A'—Cases other than Criminal Cases**

1. Application for leave to Appeal to the Supreme Court.—(1) A party desiring to appeal to the Supreme Court may apply orally for a Certificate in terms of Article 134-A of the Constitution of India immediately after the pronouncement of the judgment by the Court and the Court may, as soon as may be, after hearing the parties or their counsel, grant or refuse the same :

Provided that if an oral application for Certificate for leave to appeal under sub-rule (1) is made and rejected, no written petition shall lie.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall affect the power of the Court to grant the said Certificate on its own motion.

2. Form of Certificate.—The Registrar shall, on order of the Court directing grant of Certificate, suo motu or otherwise, issue a Certificate in Form No. 69 within three days of passing of the order.

Existing Provision

In a case falling under Article 133 (1) of the Constitution, it shall clearly state how it fulfills the requirements thereof.

In a case falling under Article 132 (1) of the Constitution, it shall state how a substantial question of law as to the interpretation of the constitution is involved.

In a case falling under Article 135 of the Constitution it shall State how appeal lies to the Supreme Court.

3. Copies:—The petition shall be accompanied by a certified copy of the judgement or final order in respect of which the certificate is sought and a certificate of the counsel that the array of parties is the same as in the case giving rise to the petition and that the Vakalatnama has already been filed.

This copy shall be for the use of the Court in addition to the copies filed in accordance with the provisions of sub-rule (1) of Rule 11 of Chapter IX and shall be a copy certified to be correct by the Head Copyist.

4. Limitation:—Article 132 of the Schedule of Limitation Act, 1963, shall, subject to the provision of any law for the time being in force, also apply to a petition for a certificate under Articles 132 (1), 133 (1) or 135 of the Constitution.

5. Notices:—(1) In connection with a Supreme Court appeal, the following notices shall be issued, namely—

- (a) notice of petition for a certificate.
- (b) notice of Judgement of petition of appeal in the Supreme Court;

Amendment

3. Consolidation of appeals.—In view of Rule 5 of Order LV of the Supreme Court Rules, 2013, no application for consolidation of appeals will be entertained by this Court.

4. Procedure for amending record after Certificate is granted.—An application for amendment of the record of the appeal by adding or substituting parties will not be entertained by the Court after the date of the order granting the Certificate and the parties desiring such amendment shall be required to move the Supreme Court in that behalf.

5. Service of notice in certain cases upon Advocates.—(1) When a party has been represented at the hearing of the appeal by an Advocate, unless the Vakalatnama of such Advocate has been cancelled with the sanction of the Court, such Advocate shall accept service of the notice in the following cases, and the service of notice in such cases on the Advocate shall be deemed sufficient notice :

- (a) of lodgment of petition of appeal; or
- (b) for inspecting the record and filing the list of documents; or

Existing Provision

(c) notice for deposit of cost of transmission of record; and

(d) notice of dispatch of record to the Supreme Court.

No other notice shall be necessary unless expressly provided for in these rules or ordered by the Court.

(2) Service of notice upon the Advocate on Record of the Appellant in the Supreme Court shall be deemed sufficient service under this Chapter. In other cases, where a party had appeared by an Advocate service of notice on such Advocate shall be deemed to be sufficient service.

(3) No process fee shall be levied in the case of notice under Clauses (b), (c) or (d) of sub-rule (1) where it may be served upon an Advocate.

6. Presentation of petition for certificate:—The petition shall be presented before the Registrar General. Where the Registrar General finds that the petition is in order, has been presented within time and is accompanied by the requisite papers, he may direct notice of petition for grant of certificate to be issued.

7. Removal of defects:—Where the Registrar General finds that the petition is not in order or is not accompanied by the requisite papers, he may either return it or may, subject to the provisions of these rules or any other law, receive it granting time for removal of the defect, provided that the time to be so granted shall not exceed the period prescribed by the Limitation Act, 1963 for such petitions. In other cases, he shall lay the case before the Court for orders.

8. Hearing of Petition:—Soon after the notice of petition has been served on the opposite party, the petition shall be listed before the Bench for final hearing.

Amendment

(c) for making deposit for the costs of transmission of the original record; or

(d) for the preparation of transcript of the record in English and for its transmission; or

(e) for the preparation and transmission of the printed transcripts of the record or photocopies thereof.

(2) Service of notice upon the Advocate-on-Record of the appellant in the Supreme Court shall be deemed sufficient service under this Chapter.

6. Procedure on receipt of the notice of lodgment of appeal in the Supreme Court.—(1) On receipt of copy of the petition of appeal from the Supreme Court, a notice of the lodgment of the petition of appeal shall be served on the respondent(s).

(2) As soon as the notice as aforesaid is served on the respondent(s), a certificate as to date or dates on which the said notice was served shall be sent to the Supreme Court.

7. Summoning of record.—The record of the case shall be summoned from the Court below, if the same is not already in the Court.

8. Notice for filing a list of documents.—(1) On receipt of the record, if any, or otherwise, the Registrar shall cause a notice to be issued to the appellant calling upon him to file, within four weeks of the service of the said notice on him, a list of the documents which he proposes to include in the paper book, a copy whereof shall be served on the respondent.

Existing Provision

9. Disposal of petition:—Such applications shall be heard and disposed of by a Judge sitting alone where leave is sought from Judgment, final order or decree passed by a single judge and, in other cases, by a Division bench. As far as possible such applications shall be laid before the single Judge or Bench which passed the judgment, or final order or decree.

10. Service of notice of lodgement of petition:—On receipt from the Supreme Court of the copy of the petition of appeal:—

(a) a notice of lodgement of the petition of appeal shall be served on the respondent and as soon as the notice is served a certificate as to date or dates on which the said notice was served shall be sent to the Supreme Court.

(b) Cost of transmission of record and balance to be refunded on an application:—Unless otherwise ordered by the Supreme Court, a notice shall issue to the appellant requiring him to deposit within a week from the date of service of this notice a sum of rupees ten on account of costs of transmission of record to the Supreme Court provided that, after meeting the cost of transmission of the record of the Court below as well as this Court, the balance, if any, shall be refunded to the appellant, on an application in this behalf being made by him.

Amendment

(2) The Registrar shall also cause a notice to be issued to the respondent intimating him the fact that a notice has already been issued to the appellant for filing the list of documents. The notice shall require the respondent to file within three weeks of the service on him of the said list, a list of such additional documents as he considers necessary for the determination of the appeal.

9. Settling of index.—(1) After the expiry of the time fixed for the filing of the list of additional documents by the respondent, the Registrar shall fix a day for the settlement of the list (hereinafter referred to as the index) of documents to be included in the appeal record and shall give notice thereof to the parties.

(2) In settling the index, the Registrar, as well as the parties concerned, shall endeavour to exclude from the record all documents that are not relevant to the subject-matter of the appeal and generally to reduce the bulk of the record as far as practicable.

10. Procedure where respondent objects to inclusion of documents.—Where the respondent objects to the inclusion of a document on the ground that it is not necessary or is irrelevant and the appellant nevertheless insists upon its inclusion, the record as finally printed shall, with a view to subsequent adjustment of cost of or incidental to the printing of the said document, indicate in the index of the paper book or otherwise the fact that the respondent has objected to the inclusion of the document and that it has been included at the instance of the appellant.

Existing Provision**Amendment**

Default to be reported to Supreme Court:—
Any default on the part of the appellant to deposit the amount to cover the cost of transmission of the record as above shall be reported to the Supreme Court for orders; and

(c) Summoning of record:—The record and proceedings of the case shall be summoned from the Court below, if the same are not already in the High Court.

(i) Filing of list of documents:—On receipt of the records a notice shall issue to the appellant calling upon him to file, within four weeks of the service upon him of the said notice a list of documents which he proposes to include in the paper book, after serving a copy thereof on each of the respondents. The appellant shall produce an acknowledgment in writing from each of the respondents that a copy of the list has been served on him.

(ii) Contents of notice to respondent:—The notice to the respondent under sub-rule (a) of Rule 10 shall also intimate to him the fact that a notice has already been issued to the appellant for filing the list of documents, and requiring him (the respondent) to file, within three weeks from the service of a copy of the list on him by the appellant, a list of such additional documents as he desires to be included in the paper book.

11. (i) Inclusion of records:—Where the decision of the appeal is likely to turn exclusively on a question of law, the appellant may apply for inclusion of such parts only of the record as may be necessary for the discussion of the same.

(ii) List to accompany application:—The application mentioned in sub-rule (i) shall in a case in which a printed record has already been prepared for the use of this Court, be accompanied by;

a list of documents already printed but considered as not relevant to the subject-matter of the appeal;

a list of documents printed on behalf of the opposite party and included in the list under Clause (i); and

11. Procedure where appellant objects to the inclusion of document.—(1) Where the appellant objects to the inclusion of a document on the ground that it is not necessary or is irrelevant and the respondent nevertheless insists upon its inclusion, the Registrar, if he is of the opinion that the document is not relevant, may direct that the said document be printed separately at the expenses of the respondent and require the respondent to deposit within such time as he may prescribe, the necessary charges therefor.

(2) If the amount so deposited is found insufficient, the Registrar may call upon the respondent to deposit additional amount or amounts within such further time as he may deem necessary.

Existing Provision

a list of documents not already printed but the printing of which is considered essential for the prosecution of the appeal, a short note being entered against each document in the list showing in what respect its inclusion is essential.

The petitioner shall serve copies of these lists on the Advocate for the opposite party.

12. Settling of Index:—After the expiry of the time fixed for the list of additional documents by the respondent, the case shall be listed before the Registrar General for the settlement of the list (hereinafter referred to as the Index) of documents to be included in the transcript of the record of appeal and shall notify the same on the notice board of the Court. No separate notices will be issued to the parties or their Advocates. In settling the index, the Registrar General as well as the parties concerned shall endeavor to exclude from the record all documents that are not relevant to the subject-matter of the appeal and generally to reduce the bulk of the record as far as practicable.

13. Procedure where respondent objects to inclusion of document:—Where the respondent objects to the inclusion of a document on the ground that it is not necessary or is irrelevant and the appellant nevertheless insists upon its inclusion, the transcript of the record as finally prepared shall, with a view to subsequent adjustment of costs of or incidental to the printing of the said document, indicate in the index of the transcript or otherwise the fact that the respondent has objected to the inclusion of the document and that it has been included at the expense of the appellant.

Amendment

(3) The question of the costs thereof will be dealt with by the Supreme Court at the time of the determination of the appeal.

12. Estimate of costs of the preparation of the transcript of record, etc.—(1) As soon as the index of the record is settled, the Registrar shall cause an estimate of the costs of the preparation of the record to be prepared and served on the appellant and require him to deposit, within 30 days of such service, the said amount. Such costs shall include the costs of transmission of transcript and translation, if any. The appellant may deposit the said amount in lump sum or in such installments as the Registrar may prescribe.

(2) After meeting the costs of the preparation and transmission of the record, the balance of the deposit, if any, shall be refunded to the appellant.

13. Where record is printed for appeal before the Court, no fresh transcript necessary.—Where the record has been printed for the purpose of the appeal before the Court and sufficient number of copies of the said printed record is available, no fresh transcript of the record shall be necessary except of such additional papers as may be required.

Existing Provision

14. Procedure where appellant objects to inclusion of documents:—Where the appellant objects to the inclusion of a document on the ground that it is not necessary or is irrelevant and the respondent nevertheless insists upon its inclusion, the Registrar General, if he is of the opinion that the document is not relevant, may direct that the said document be included separately at the expense of the respondent and require the respondent to deposit within such time as he may prescribe the necessary charges thereof. If the amount so deposited is found insufficient the Registrar General may call upon the respondent to deposit additional amount or amounts within such further time as he may deem necessary. The question of the costs thereof will be dealt with by the Supreme Court at the time of the determination of the appeal.

15. Estimate of costs of the preparation of the transcript of record, etc.:—As soon as the index of the record is settled, the Registrar General shall cause an estimate of the costs of the preparation of the transcript of the record (and of printing or cyclostyling the record, where it is required to be printed or cyclostyled) to be prepared and served on the appellant and shall require him to deposit within thirty days of such service the said amount. Such costs shall include the costs of translation, if any. The appellant may deposit the said amount in lump sum or in such installments as the Registrar General may prescribe.

16. Where record is printed for High Court appeal, no fresh transcript necessary:—Where the record has been printed for the purpose of the appeal before the High Court and sufficient number of copies of the said printed record is available, no fresh transcript of the record shall be necessary except of such additional papers as may be required.

Amendment

14. Registrar may call for additional deposit if deposit made is insufficient.—If at any time during the preparation of the record the amount deposited is found insufficient, the Registrar shall call upon the appellant to deposit such further sum as may be necessary within such further time as may be deemed fit, but not exceeding twenty eight days in the aggregate.

15. Procedure on appellant making default in making deposit.—(1) Where the appellant fails to make the required deposit, the preparation of the record shall be suspended and the Registrar shall not proceed with the preparation thereof without an order in this behalf of this Court.

(2) The Court may give such accommodation in the matter of time for making the deposit as it deems proper and if the appellant continues the default in spite of the orders of this Court, the Registrar shall obtain an order from the Court for reporting the default to the Supreme Court and report accordingly.

16. Preparation of record.—(1) Unless the Supreme Court so directs, the record shall not be printed or photocopied in this Court.

(2) Where the Supreme Court directs that the record be printed in this Court, the same shall be printed in accordance with the rules contained in the First Schedule to the Supreme Court Rules, 2013.

(3) Where the paper-book pertaining to the appeal is not likely to consist of more than 200 pages, the Registrar may, instead of having the record printed, have it photocopied.

Existing Provision**Amendment**

17. Registrar General may call for additional deposit, if deposit made is insufficient:—If at any time during the preparation of the transcript of the record (or printing or cyclostyling of the record, where it is required to be printed or cyclostyled) the amount deposited is found insufficient, the Registrar General shall call upon the appellant to deposit such further sum as may be necessary within such further time as may be deemed fit but not exceeding 8 days in the aggregate.

18. Procedure on appellant making default in making deposit:—Where the appellant fails to make the required deposit, the preparation of the transcript of the record (and the printing or the cyclostyling of the record, where the same is required to be printed or cyclostyled) shall be suspended and the Registrar General shall not proceed therewith without an order in this behalf of the Supreme Court.

19. (i) Record not to be printed unless ordered by the Supreme Court:—Unless the Supreme Court so directs the record shall not be printed or cyclostyled in this court.

(ii) Rules regarding printing and cyclostyling:—Where the Supreme court directs that the record be printed or cyclostyled in this court the same shall be printed or cyclostyled in accordance with the rules in the First Schedule to the Supreme Court Rules, 1966.

(4) Unless a party informs its requirements before the printing or the photocopying is undertaken, each party shall be entitled to three copies of the record for its use.

(5) Where the records are printed for the purpose of the appeal before this Court and the said record be in English, this Court shall prepare 10 extra copies in addition to the number of copies required by this Court for use in the Supreme Court.

17. Certification of record.—The Registrar shall, when the record has been made ready, certify the same and give notice to the parties of the certification of the record and append to the record a certificate showing the amount of expenses incurred by the party concerned for the preparation of the record.

18. Translation of papers.—All documents included in the list which are not in English and are not already translated shall be translated into English. All such translations shall be made or certified as correct by one of the Court translator.

19. Where depositions of witnesses are to be translated.—The deposition of witnesses in the original languages shall not be translated in cases in which the notes of the substance of the depositions are taken in English by the Courts below, unless any one of the parties desires and shows sufficient cause to the Registrar that particular depositions should be translated and the Registrar orders that they should be translated.

Existing Provision

(iii) Record may be cyclostyled if consisting less than 200 pages:—Where the appeal paper book is not likely to consist of more than 200 pages, the Registrar General may, instead of having the record printed, have it cyclostyled.

(iv) Number of copies for the use of the Supreme Court:—Unless otherwise directed by the Supreme Court at least 20 copies of the record shall be prepared for the use of the Supreme Court.

(v) Number of copies for the parties—Unless party informs its requirements before the printing or the cyclostyling is undertaken, each party shall be entitled to three copies of the record for its use.

20. Translation of papers:—All documents included in the list which are not in English and are not already translated shall be translated into English. All such translations shall be made or certified as correct by one of the court translator.

21. (i) Transcript of the record to be transmitted to Supreme Court within six months:—The Registrar General shall, within six months from the date of the service on the respondent of the notice of the petition of appeal, transmit to the Supreme Court in triplicate a transcript in English of their record proper of the appeal to be laid before the Supreme Court, one copy of which shall be duly authenticated by appending to certificate to the same under his signature and the seal of this High Court. If for reason the same cannot be transmitted within the period of six months mentioned above, the Registrar General shall report the facts to the Supreme Court and obtain necessary extension of time for transmitting the same.

(ii) Certificate of expense to be appended to the transcript or forwarded separately:—The Registrar General shall also append to the transcript of the record or separately forward a certificate, showing the amount of expenses incurred by the parties concerned for the preparation and the transmission of the transcript of the record.

Amendment

20. Procedure where parties disagree in regard to translations.—The parties shall be invited from time to time to inspect the translations, and in case of disagreement, the points in dispute, which must be stated in writing, shall be submitted within one week to the Registrar for his decision, and the Registrar, after perusal of the same, shall decide the point in dispute. The writings submitted by the parties mentioning the points in dispute with the decision of the Registrar noted thereunder shall form part of the record.

21. Rate of fees for preparation of the transcript, printing, photocopying and translation of record.—For preparing the transcript of record (and for printing or photocopying the same, where it is required to be printed or photocopied) fees shall be charged on following rates—

(a) An estimating fee of Rs. 16 in Court fee labels shall be paid by the appellant along with the list of documents filed under Rule 8.

(b) Translating Hindi or Urdu portions of record—Rs. 4 for every page or part thereof.

(c) Examining Hindi or Urdu portions of record already translated—Rs. 2 for every page or part thereof.

(d) Translation of portions of record in other languages—Rs. 6 for every page or part thereof.

(e) Examining portion of record of other languages already translated—Rs. 3 for every page or part thereof.

Existing Provision**Amendment**

(f) Photocopying of documents for preparation of the transcript of the record—Re. 1 for every page or part thereof.

(g) Comparing copies of documents for the preparation of transcript of the record—Re. 1 for every page or part thereof.

(h) Writing Head—Notes to documents in the transcript of the record—Re. 1 for each head note.

(i) Preparation of Index—Re. 1 per item.

(j) Examination of proofs where the record is required to be printed or photocopied—Re. 1 for every page printed or photocopied.

(k) Certifying of transcript of the record or of printed or photocopied record by the Deputy Registrar—Re. 1 for every 10 pages or part thereof.

(l) Printing charges—Actual cost not less than Rs. 7 per page.

(m) Photocopying charges—Rs. 2 per page or part thereof.

22. Form of notice of transmission of the transcription to the parties:—When the transcript has been made ready, the Registrar General shall certify the same and give notice to the parties of the certification and the transmission of the transcript of the record (or of the printed or cyclostyled record, where it is required to be printed or cyclostyled record) and thereafter shall send a certificate to the Supreme Court as to the date or dates on which the notice has been served on the parties in form No. X of Schedule A appended to this Chapter.

22. Transmission of original record and transcript thereof.—(1) The Registrar shall, if specifically ordered by the Supreme Court, transmit, at the expense of the appellant, the original record of the case, including the record of the Courts below, to the Supreme Court.

(2) The Registrar shall, where the proceedings from which the appeal arises were had in courts below in a language other than English, within six months from the date of the service on the respondent of the notice of petition of appeal, transmit to the Supreme Court in triplicate a transcript in English of the record proper of the appeal to be laid before the Supreme Court, one copy of which shall be duly authenticated by appending the certificate to the same under his signature and the seal of this Court.

(3) The Registrar shall also append to the transcript the certificate as mentioned in Rule 17.

Existing Provision

23. Procedure regarding investigation of pauperism of applicants to Supreme Court:—When an order of the Supreme Court directing investigating into the pauperism of an appellant is received, it shall be laid before the court for orders as to whether the necessary enquiry in the matter is to be made by the Court itself or by a subordinate court. In the latter case the court shall, while forwarding the findings of the subordinate court to the Supreme Court record its own opinion therein.

24. Notice to appellant where special leave granted by the Supreme Court:—As soon as certified copy of the order of the Supreme Court granting special leave to appeal has been received by the Court, the Registrar General shall give immediate notice thereof to the appellant.

25. Application of Rules in this Chapter and Order XLV of the Code to cases in which special leave has been granted:—Subject to such special directions as may be given by the Supreme Court the provisions of the rules contained in this Chapter and Order XLV of the Code of Civil Procedure shall, so far as may be and with such modifications and adaptations as may be found necessary apply to a case in which special leave to appeal has been granted by the Supreme Court.

26. Suits on death of party by or against minor:—Where any party to the petition dies before the certificate is granted the provisions contained in Rules 1 to 6 and 9 of Order XXII and Order XXXII of the Code shall, so far as may be and with necessary modifications and adaptations, apply.

Amendment

23. Procedure regarding investigation of indigency of applicant to the Supreme Court.—When an order of the Supreme Court, under Rule 3 of Order XVIII of the Supreme Court Rules, 2013, directing investigation into the indigency of an applicant is received, it shall be laid before the Court for orders as to whether the necessary investigation in the matter is to be made, after notice to the interested parties, by the Court itself or by a Court subordinate to it. The Court shall submit a report thereon to the Supreme Court within such time as may be fixed by the order made by the Supreme Court:

Provided that in the latter case, the Court shall, while forwarding the findings of the subordinate Court to the Supreme Court, record its own opinion therein.

24. Taking of evidence in case of dispute as to legal representative.—Where it becomes necessary to take evidence in order to determine whether any person is or is not proper person to be substituted, or entered, on the record in place of, or in addition to, the party on record, the Court may either take such evidence itself or direct any lower Court to take such evidence and to return it together with its findings and reasons and take such findings and reasons into consideration in determining the questions.

25. Notice when not required.—Nothing in this chapter requiring any notice to be served on or given to an opposite party or respondent shall be deemed to require any notice to be served on or given to the legal representative of any deceased opposite party or deceased respondent in a case, where such opposite party or respondent did not appear either at the hearing in the Court whose decree is complained of or at any proceedings subsequent to the decree of that Court.

Section 'B' Criminal Cases

26. Application for leave to Appeal to the Supreme Court.—(1) A party desiring to appeal to the Supreme Court may apply orally for a Certificate in terms of Article 134-A of the Constitution of India immediately after the pronouncement of the judgment by the Court and the Court may, as soon as may be, after hearing the parties or their counsel, grant or refuse the same :

Provided that if an oral application for Certificate for leave to appeal under sub-rule (1) is made and rejected, no written petition shall lie.

Existing Provision

27. Taking of evidence in case of dispute as to legal representative:—Where it becomes necessary to take evidence in order to determine whether any person is or is not proper person to be substituted, or entered, on the record in place of, or in addition to, the party on record, the court may either take such evidence itself or direct any lower court to take such evidence and to return it together with its findings and reasons and take such findings and reasons into consideration in determining the questions.

SECTION 'B'-CRIMINAL CASES

28. Applications for a certificate under Art. 132 (1) or Art. 134 (1) (c) of the Constitution:—An application for a certificate under Art 132 (1) or 134 (1) (c) of the Constitution in criminal proceedings shall be made in writing stating the grounds on which the leave is sought, within sixty days from the date of the judgment, final order or sentence passed by the court. The provisions of Secs. 4 and 5 of the Limitation Act, 1963 shall apply to such an application and the remaining provisions shall not apply.

In computing the period of limitation prescribed in the preceding paragraph, the time requisite for obtaining a copy of the judgment, final order or sentence passed by the court shall be excluded.

Such application shall be heard and disposed of by a Judge sitting alone where leave is sought from the Judgment, final order or sentence passed by a single Judge and in other cases by a Division Bench. As far as possible such application shall be laid before the single Judge or Bench which passed the judgment, final order or the sentence.

Amendment

(2) Nothing in sub-rule (1) shall affect the power of the Court to grant the said Certificate on its own motion.

27. Cost of preparation, transmission etc. of the transcript of record.—Except as otherwise ordered by the Supreme Court, the preparation of the transcript of the record (and of the printed or the photocopied record, where the same is required to the printed or photocopied) and the transmission thereof shall be at the expense of the appellant :

Provided that in appeals involving sentence of death, the record shall be printed at the expense of the State.

28. Preparation of record.—(1) Where the records are printed for the purpose of the appeal before this Court, the Court shall prepare 10 extra copies in addition to the number of copies required by the Court for use in the Supreme Court, if the said record be in English.

(2) Where the record has been printed for the purposes of appeal before this Court, all available copies of the printed record except one, if the record be in English, shall be dispatched to the Supreme Court along with the entire original record, including the records of the Court below. One of such copies shall be duly authenticated by the Registrar :

Provided that in criminal appeals other than those involving sentence of life imprisonment or death penalty, the original record of the case, including the record of the Courts below, shall be dispatched only when specifically ordered by the Supreme Court.

Existing Provision

Provided that where the applicant has been sentenced to a term of imprisonment the application shall not be entertained until the applicant has surrendered and in proof thereof has filed a certificate either of the Magistrate before whom he has surrendered or of the Superintendent or Jailor of the Jail in which he has been lodged unless the court on a written application for that purpose orders otherwise. Where the application for a certificate is accompanied by such an application both the applications shall be listed together before the court.

29. Intimation of application to Sessions Judge:—As soon as an application for grant of a certificate under Art. 134 of the Constitution of India from or on behalf of the condemned prisoner is received the fact shall be notified to the Sessions Judge concerned to enable him to defer execution of the sentence of death. Intimation will again be sent to the Sessions Judge when application is finally disposed of.

30. Appeal to Supreme Court on cases covered under Sec. 426, Cr.P.C.:—(1) On the applicants executing a bond with or without sureties undertaking to lodge an appeal in the Supreme Court within prescribed time, the Court may—

(1) in a case covered by Section 426 (2-A) of the Code of Criminal Procedure order that the appellant be released on bail for a period sufficient in the opinion of the court to enable him to present the appeal and obtain the order, of the Supreme Court under Section 426 (1) ;

(2) in cases under Section 426 (2-B) order that pending the appeal, the sentence or order appealed against be suspended and also if the applicant is in confinement, that he be released on bail ;

Amendment

(3) As soon as the record is ready, the Registrar shall give notice thereof to the parties to the appeal and send to the Registrar of the Supreme Court a certificate as to date or dates on which the notice has been served.

(4) Where the appellant fails to take necessary steps to have the record prepared and transmitted to the Supreme Court with due diligence, the Registrar shall report the default to the Registrar of the Supreme Court.

29. Number of copies to be printed where record is directed to be printed.—In the event of the Supreme Court ordering the printing of the record under the supervision of the Registrar of this Court, he shall dispatch to the Registrar of the Supreme Court, unless otherwise directed, not less than 15 copies where the appeal raises a question as to the interpretation of the Constitution, and not less than 10 copies in other cases.

30. Documents translated for High Court appeal need not be translated again.—For the purposes of the transcript of the record, such of the documents in vernacular as have already been translated for the purposes of the High Court Appeal and which are included in the High Court Appeal Paper-Book need not be translated again.

Existing Provision**Amendment**

Provided that a person applying under Section 426 (2-B) shall make an averment to the effect that he has not made a similar application to the Supreme Court.

(2) No application for bail or suspension of sentence or order shall be entertained unless the applicant has surrendered himself in court and has noted the fact in his application.

(3) Where the application is by the State, no such bond shall be required before an order under this rule is made.

(4) A certified copy of the order under Section 426 (2-B) granting bail on suspending operation of the sentence or order appealed against shall be transmitted to the Registrar, Supreme Court without delay.

31. Preparation and upkeep of transcribed records:—After the appeal has been lodged in the Supreme Court and copy of the petition of appeal has been received from the Registrar General of that court, the Registrar General shall, with all convenience spend, cause a transcript of the record to be prepared keeping in view the period within which copies of the record are required to be dispatched to the Supreme Court in cases falling under Art. 134 (1) (a) and (b) of the Constitution.

32. Notice of dispatch of record:—As soon as the requisite number of copies of the transcript and the record have been dispatched to the Supreme Court, the Registrar General shall give notice thereof to the parties.

33. Application of certain rules in Section 'A'- Rules 3, 5, 19 and 20 of Section 'A' shall with such modifications and adaptations as may be found necessary, also apply to appeals to the Supreme Court in criminal matters.

31. Special time-limit for preparation and transmission of record in cases involving sentence of death.—(1) In all cases involving a sentence of death, the printed record shall be made ready and dispatched to the Supreme Court within a period of 60 days after the receipt of the intimation from the Registrar of the Supreme Court of the filing of the petition of appeal or of the order granting special leave to appeal.

(2) In cases where such record cannot be dispatched within 60 days as stated in sub-rule (1), the Registrar shall explain the circumstances under which it cannot be so dispatched and obtain extension of time from the Supreme Court.

32. Interpretation.—For the purposes of Rules 28 to 31 (both inclusive) :

(a) the original record shall not include judgments of the High Court and the Courts below, but only duly authenticated copies thereof.

(b) printing includes photocopying and typing, and printed record includes photocopied or typed record.

33. Application of Rules 5 to 22.—Except where specifically otherwise provided in this Section, the provisions of Rules 5 to 22, with necessary modifications and adaptations, shall apply to appeals in criminal cases on the Certificate issued by this Court.

Existing Provision**Amendment****SECTION 'C'-SUPREME COURT DECREES****Section 'C '-Special Leave Petition (Civil)**

34. Enforcement of Supreme Court decrees:—
The enforcement of decrees passed or decrees made by the Supreme Court shall be made in accordance with the provisions contained in the Supreme Court (Decree and Orders) Enforcement Order, 1934, reproduced in the Appendix to this Chapter.

34. Application Rules 5 to 25.—The provisions of Rules 5 to 25 (both inclusive), with necessary modifications and adaptations, shall apply to Civil Appeals by Special Leave to the Supreme Court.

Section 'D'-Special Leave Petition (Criminal)

35. Petitioner intending to apply for special leave to be supplied copy of judgment or order free of cost.—On application by the petitioner intending to apply for special leave of the Supreme Court in criminal proceedings and appeals, a certified copy of the judgment or order sought to be appealed from shall be supplied to him free of cost.

36. Procedure on receipt of order granting special leave.—On receipt of the order granting special leave to appeal to the Supreme Court, the Registrar shall require the office to take necessary steps to have the record of the case transmitted to the Supreme Court in accordance with the directions contained in the order granting special leave.

37. Application of Rules 26 to 33.—The provisions of Rules 26 to 33 (both inclusive), with necessary modifications and adaptations, shall apply to criminal appeals by special leave to the Supreme Court.

Section 'E'-Supreme Court Decrees

38. Enforcement of Supreme Court decrees.—The enforcement of decrees passed or decrees made by the Supreme Court shall be made in accordance with the provisions contained in Supreme Court (Decree and Orders) Enforcement Order, 1954.

5. Amendment of Form No. 69.-Form No. 69 of Volume II of the Rules shall be substituted as follows :

Existing Provision	Amendment
No. 69-CERTIFICATE THAT THE CASE IS FIT FOR APPEAL TO SUPREME COURT (CHAPER XXIII, RULE 9)	No. 69-CERTIFICATE THAT THE CASE IS FIT FOR APPEAL TO SUPREME COURT (CHAPER XXIII, RULE 2)
Civil Side [ORDER XLV, RULE 7 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908]	[ARTICLE 132 OR 133 OR 134 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]
or	
[ARTICLE 132 OR 133 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]	
Appellate Jurisdiction	Appellate Jurisdiction
<p><i>In the matter of</i></p> <p>Application no. _____ of 19 _____ , for leave to appeal to the Supreme Court of India from the decree/final order of this Court, dated theday of 19 _____ , in no.of 19 _____</p> <p><i>Applicant,</i></p> <p><i>versus</i></p> <p><i>Opposite-party.</i></p>	<p><i>In the matter of</i></p> <p>Application no. _____ of _____ , for leave to appeal to the Supreme Court of India from the decree/final order of this Court, dated theday of of inno.of <i>Applicant,</i></p> <p><i>versus</i></p> <p><i>Opposite-party.</i></p>
<p>Upon the hearing of the appplication ofapplicant above-mentioned for leave to appeal to the Supreme Court of India from the abovenoted decree/final order of this Court, by a Division Court constituted by the Hon'ble.....and the Hon'ble.....appearing on behalf of the applicant, andappearing on behalf of the opposite-party,</p> <p>It is certified-</p> <p>That the case fulfils the requirements of Section 110 of the Code of Civil Procedure, 1908/Article 133(1)(a)/(b) of the Constitution of India.</p>	<p>Upon the hearing of the appplication ofapplicant above-mentioned for leave to appeal to the Supreme Court of India from the abovenoted decree/final order of this Court, by a Division Court constituted by the Hon'ble.....and the Hon'ble.....,appearing on behalf of the applicant, andappearing on behalf of the opposite-party,</p> <p>It is certified-</p> <p>That the case fulfils the requirements of clause (1) of Article 132 of the Constitution of India.</p>

or

That the case is a fit one for appeal under Article 132(1)/133(1) (c) of the Constitution of India.

or

That the case fulfils the requirements of clause (1) of Article 133 of the Constitution of India.

or

That the case fulfils the requirements of sub-clause (c) of clause (1) of Article 134.

Given under my hand and the seal of the Court, this day*ofin the year one thousand nine hundred and

Advocate for Applicant-

Date

Advocate for Opposite-Party-

Date

Deputy Registrar,
Allahabad/Lucknow

Given under my hand and the seal of the Court, this day*ofin the year.....

Advocate for Applicant-

Date

Advocate for Opposite-Party-

Date

Registrar,
Allahabad/Lucknow

*Here enter the date of the judgment or order upon which the certificate is founded.

*Here enter the date of the judgment or order upon which the certificate is founded.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

12 जुलाई, 2021 ई०

सं० 3017/आठ-वि०भू०अ०अ०(सि०) मीरजापुर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर सोनभद्र की राय है, कि करैला रोड से शक्तिनगर रेल लाईन दोहरीकरण के लिये जनपद सोनभद्र, तहसील दुध्दी, ग्राम अनपरा की रकबा 1.0890 हे० भूमि की आवश्यकता है।

Notification under section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Collector, Sonebhadra satisfied that a total of 1.0890 hectare land is required in the Village-Anapara, Pargana-Singrauli, Tehsil-Dudhi, Distt. Sonebhadra is required for public purpose, namely Karaila Road to Shaktinagar Rail Line Doubling Ministry of Railway.

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 08 जुलाई, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

Social impact assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendation to the appropriate government which has approved its recommendation on date 08-07-2021.

3-सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

"करैला रोड से शक्तिनगर रेल लाईन दोहरीकरण के निर्माण से नकारात्मक प्रभाव के सापेक्ष सकारात्मक प्रभाव काफी अधिक है प्रभावित परिवारों को इस सामाजिक समाघात आंकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी शमन प्रक्रिया को अपनाते हुये वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिये। सामाजिक समाघात आंकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी शमन प्रक्रिया के अनुसार भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जाय।"

The summary of the social impact assessment report as follow :

Based on the social impact assessment carried out by the agency, it is evident that the positive impacts associated with construction of Karaila Road to Shaktinagar Rail Line Doubling Ministry of Railway are more than negative impacts, procedure suggested in the social impact assessment shall be followed while doing land acquisition from the indentified families all the measures suggested in the land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 shall be followed to ensure fair compensation and Rehabilitation and Resettlement policy from the identified families in accordance with the procedure outlined in social impact assessment report.

4-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

No body effected for this project.

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose :

अनुसूची / SCHEDULE

जनपद / District	तहसील / Tehsil	परगना / Pargana	ग्राम / Village	गाटा सं0 / Gata No.	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल / Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर Hectare
सोनभद्र Sonebhadra	दुद्धी Dudhi	सिंगरौली Singrauli	अनपरा Anapara	209-च	0.2910
				211-ख	0.2800
				211-ङ	0.2780
				212	0.0400
				234-क	0.0120
				234-ग	0.0580
				338-क	0.0870
				272	0.0430
				योग .	1.0890
				Total .	

6-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिये समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary step to entre upon and survey of land take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Sonebhadra/Special Land Acquisition Office (Irrigation), Mirzapur.

शिव प्रसाद,
कलेक्टर सोनभद्र/मीरजापुर,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)।

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2021 ई०

सं० 589/आठ-वि०भू०अ०अ०/अधिसूचना/बस्ती/2021—सरयू नहर परियोजना द्वारा आपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत गैप्स को पूर्ण करने हेतु जनपद-बस्ती ग्राम-बानगढ़, बेलसूही, खडौवाजाट, भौंसा, पडरी, असियापार, झ्यूहारी, रानीपुर, भिटियाखुर्द, हरैया, कोहडवा, नगहरा, नटाईकला, धर्मपुरवा, महुवापार, परसाखाल, आमा, आहर, मधवापुर, रानीपुर, मुडिलवा, छपियाशुक्ल, रानीपुर, बैदोलिया व मस्जिदिया में स्थित 4.38015 हे० भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 399/आठ-वि०भू०अ०अ०/अधिसूचना/बस्ती/2021/दिनांक 16 जुलाई, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक: 24 जुलाई, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ बस्ती द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24 जुलाई, 2021 पर विचारोपरान्त धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है, तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित

जिला बस्ती की तहसील सदर, रुधौली, भानपुर, हरैया की सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। सरयू नहर परियोजना द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा सरयू परियोजना के अन्तर्गत नहरों के गैप्स के निर्माण के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितबद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बस्ती	बस्ती सदर	बस्ती पूरब	बानगढ़	79	हेक्टेयर 0.08000
				284	0.04625
				291	0.02600
				489	0.27600
		नगर पूरब	खड़ौवाजाट	338	0.03700
				340	0.00800
				64-क	0.01000
				20	0.00300
		महुली पश्चिम	पड़री	97	0.11250
				218	0.00120
				159	0.12260
				असियापार डिवहारी	
		नगर पूरब	रानीपुर	105-मि0	0.08300
				36-मि0	0.07875
				157	0.07275
				159	0.01900
		बस्ती पूरब	भैसा	38	0.12100
				3-मि0	0.03600
				86	0.02600
				518	0.01440
		महुली पश्चिम	हरैया	137	0.41100
				कोहड़वा	
				169	0.04400
				165	0.03800
		रुधौली	बस्ती पूरब	177	0.01200
				74	0.12000
				220	0.04320
				256	0.11000
	बस्ती सदर	मगहर पश्चिम	नटाईकला	288	0.21500
				धर्मपुरवा	

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बस्ती	भानपुर		महुआपार	121	0.06400
		नगर पूरब	परसाखाल	235	0.06200
				392	0.03000
		बस्ती पूरब	आमा	217	0.09100
				220	0.00400
				221	0.00800
			आहर	591	0.04700
	हरैया	बस्ती पश्चिम	मधवापुर	60	0.25000
		नगर पश्चिम	रानीपुर	114	0.14000
				111	0.31000
				189	0.03600
				447	0.11800
		बस्ती पश्चिम	मुड़िलवा	8	0.04500
		अमोढ़ा	छपियाशुक्ल	21	0.00400
				169	0.00700
				155	0.15200
				168	0.18400
				153	0.16900
				154	0.05250
		नगर पश्चिम	रानीपुर	31	0.04600
		बस्ती पश्चिम	बैदोलिया	3	0.04800
				216	0.04500
			मस्जिदिया	193	0.15500
				127	0.14000
				203	0.00600

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बस्ती	बस्ती सदर	बस्ती पूरब	बानगढ़	शून्य	शून्य
			बेलसूही	शून्य	शून्य
		नगर पूरब	खड़ौवाजाट	शून्य	शून्य
		बस्ती पूरब	भैंसा	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बस्ती	बस्ती सदर	महुली पश्चिम	पड़री	शून्य	शून्य
			असियापार डिवहारी	शून्य	शून्य
		नगर पूरब	रानीपुर	शून्य	शून्य
		बस्ती पूरब	भिटियाखुर्द	शून्य	शून्य
			भैसा	शून्य	शून्य
		महुली पश्चिम	हरैया	शून्य	शून्य
			कोहड़वा	शून्य	शून्य
	रुधौली	बस्ती पूरब	नगहरा	शून्य	शून्य
	बस्ती सदर	मगहर पश्चिम	नटाईकला	शून्य	शून्य
		बस्ती पूरब	धर्मपुरवा	शून्य	शून्य
	भानपुर		महुआपार	शून्य	शून्य
		नगर पूरब	परसाखाल	शून्य	शून्य
		बस्ती पूरब	आमा	शून्य	शून्य
			आहर	शून्य	शून्य
	हरैया	बस्ती पश्चिम	मधवापुर	शून्य	शून्य
		नगर पश्चिम	रानीपुर	शून्य	शून्य
		बस्ती पश्चिम	मुडिलवा	शून्य	शून्य
		अमोढ़ा	छपियाशुक्ल	शून्य	शून्य
		नगर पश्चिम	रानीपुर	शून्य	शून्य
		बस्ती पश्चिम	बैदोलिया	शून्य	शून्य
			मस्जिदिया	शून्य	शून्य

नोट—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, बस्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, बस्ती।

NOTIFICATION

Dated September 27, 2021

No. 589/VIII-S.L.A.O./Notification/Basti/2020-21—Whereas preliminary notification No. 399/VIII-S.L.A.O./Notification/Basti /2020-21, dated July 16, 2021 was issued under section-11 sub-section (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 4.38015 hectares of land in Village-Bangard, Belsuhi, Khaduwa jatt, Bhaisa, Padri, Ashiyapar duehari, Ranipur, Bhitya Khurd, Harraiya, Khodhawa, Nagahra, Nataikala, Dharampurwa, Mahuwapar, Parsakhala, Aama, Aahar, Madhwapur, Ranipur, Mudilwa, Chapiya Shukala, Baidoliya, Masjidiya District Basti is required for public purpose namely gapes under Saryu Nahar Prayojana and lastly published on dated July 24, 2021.

After considering the report of the Collector dated July 16, 2021 submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the act, the Governor is pleased to declare under section- 19 (1) of the act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the act, to direct the Collector of Basti to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. No any interested person is getting displaced in the acquisition process of proposed land for gaps of Saryu Nahar Prayojana.

SCHEDULE "A"
(Land under proposed Acquisition)

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Basti	Basti Sadar	Basti Purab	Bangard	79	0.08000
				284	0.04625
				291	0.02600
		"	Belsuhi	489	0.27600
		"	Khaduwa Jatt	338	0.03700
				340	0.00800
			Bhiasa	64-क	0.01000
		Mahuli Pachim	Padri	20	0.00300
				97	0.11250
				218	0.00120
		"	Ashiyapar Duehari	159	0.12260
		Nagar Purab	Ranipur	105-मि०	0.08300
		Basti Purab	Bhitya Khurd	36-मि०	0.07875
				157	0.07275
		"		159	0.01900
				38	0.12100
			Bhaisa	3-मि०	0.03600
				86	0.02600
		Mahuli Pachim	Harraiya	518	0.01440
			Khodhauwa	137	0.41100
	Rudhauri	Basti Purab	Nagahara	169	0.04400
				165	0.03800
				177	0.01200
	Basti Sadar	Maghar Pachim	Nataikala	74	0.12000
		"		220	0.04320
				256	0.11000
		Basti Purab	Dharampurwa	288	0.21500

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Basti	Bhanpur	Basti Purab	Mahuwapar	121	0.06400
		Nagar Purab	Parsakhal	235	0.06200
				392	0.03000
		Basti Purab	Aama	217	0.09100
		"		220	0.00400
				221	0.00800
			Aahar	591	0.04700
	Harraiya	Basti Pachim	Madhwapur	60	0.25000
		Nagar Pachim	Ranipur	114	0.14000
				111	0.31000
				189	0.03600
				447	0.11800
			Mudelwa	8	0.04500
		Amoraha	Chapiya Shukla	21	0.00400
				169	0.00700
		"		155	0.15200
				168	0.18400
		"		153	0.16900
				154	0.05250
		Nagar Pachim	Ranipur	31	0.04600
			Baidoliya	3	0.04800
				216	0.04500
			Masjidiya	193	0.15500
				127	0.14000
				203	0.00600

SCHEDULE "B"**(Market land in the area of rehabilitation and resettlement for displaced families)**

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Basti	Basti Sadar	Basti Purab	Bangard	Zero	Zero
			Belsuhi	Zero	Zero
			Khaduwa Jatt	Zero	Zero

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Basti	Basti Sadar	Basti Purab	Bhiasha	Zero	Zero
		Mahuli Pachim	Padri	Zero	Zero
			Ashiyapar Duehari	Zero	Zero
		Nagar Purab	Ranipur	Zero	Zero
		Basti Purab	Bhitya Khurd	Zero	Zero
			Bhaisa	Zero	Zero
		Mahuli Pachim	Harraiya	Zero	Zero
			Khodhauwa	Zero	Zero
	Rudhauili	Basti Purab	Nagahara	Zero	Zero
	Basti sadar	Maghar Pachim	Nataikala	Zero	Zero
		Basti Purab	Dharampurwa	Zero	Zero
			Mahuwapar	Zero	Zero
		Nagar Purab	Parsakhal	Zero	Zero
		Basti Purab	Aama	Zero	Zero
			Aahar	Zero	Zero
	Harraiya	Basti Pachim	Madhwapur	Zero	Zero
		Nagar Pachim	Ranipur	Zero	Zero
			Mudelwa	Zero	Zero
		Amodha	Chapiya Shukla	Zero	Zero
		Nagar Pachim	Ranipur	Zero	Zero
			Baidoliya	Zero	Zero
			Masjidiya	Zero	Zero

NOTE –A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Basti for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE
COLLECTOR,
Basti.

अधिसूचना

28 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1086/8(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित के लिये अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के निर्माण हेतु जिला लखनऊ में कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना सेक्टर ओ0 की 944.50 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 966/8(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ, दिनांक 04 सितम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी है।

उक्त अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला लखनऊ, तहसील सरोजनीनगर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयर पोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के निर्माण हेतु जिला लखनऊ में कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना सेक्टर ओ० की 944.50 वर्गमीटर भूमि अर्जन से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है)।

अनुसूची-"क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर ओ० मानसरोवर योजना	सी-4/55 सी-4/56 सी-4/57 सी-4/58 सी-4/64 सी-4/72 सी-4/73 सी-4/97 सी-4/98	9.00 22.00 30.00 37.50 200.00 130.00 200.00 196.00 120.00
				योग . .	944.50

अनुसूची-"ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	सरोजनीनगर	बिजनौर	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2021 ई०

सं० 1480/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०) सं०सं०, लखनऊ—“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर निर्माण हेतु जिला लखनऊ में ग्राम बेहसा की 637.323 वर्ग मीटर भूमि की अत्यावश्यकता है।”

2-परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के प्रावधान लागू होंगे।

3-प्रस्तावित भूमि के अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 9 में दी गयी छूट के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 40 की उपधारा 4 में वर्णित है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचना करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नाम काश्तकार/पिता/ पति का नाम	स्थायी पता	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ	सरोजनीनगर	बिजनौर	बेहसा	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री बी0एल0 गुप्ता श्री मनीष सैनी पुत्र स्व0 देवराज सैनी	307/161, मातादीन रोड, सआदतगंज, लखनऊ 559/के एच ए/87/श्रीनगर, श्रंगार नगर के पास आलमबाग, लखनऊ	1064-मि0 1064-मि0	20.55 91.52
				श्रीमती ममता राय पत्नी श्री मुन्ना कुमार राय	कोतवाली कृष्णानगर, टाइप-1, कमरा नं0-1, कानपुर रोड, लखनऊ	1064-मि0	101.011
				श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री हीरा लाल यादव	582-क/के एन 1064-5ए न्यू बेहसा, सरोजनीनगर, लखनऊ	1064-मि0	91.142
				श्रीमती दीपाली गोयल पत्नी श्री अंकित गोयल	ए-160 ओमैक्स सिटी, शहीदपथ लखनऊ	1064-मि0	111.75
				श्रीमती रोशनी कुमारी पत्नी श्री अशोक गुप्ता	ग्राम धनगुवा, पो0 धौरडीन्हा, जिला सेतास, बिहार	1064-मि0	111.65
				श्री मोती राय पुत्र श्री बंशी राय	म0 नं0 4 टाइप 3 एयरपोर्ट कालोनी, हिन्द नगर, कानपुर रोड, लखनऊ	1068	109.70
योग. .							637.323

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-प्रस्तावित भूमि के अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा 4 के अनुसार अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपबन्ध लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है।

7-अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ के कक्ष संख्या-42 स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 अक्टूबर, 2021 ई० (आश्विन 10, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, लोनी-गाजियाबाद

17 जुलाई, 2021 ई०

सं० 1030/न०पा०परि०-लो०गा०/2021-22-संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 298 (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर नगर पालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद अपनी सीमा में प्रतिलिपि शुल्क उपविधि बनायी है। उपविधियों का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 300 (1) के अधीन समस्त नगरवासियों से आपत्ति एवं सुझावों को आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र, "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" के अंक दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें नगरवासियों से दावे आपत्ति प्राप्त करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था। उक्त के क्रम निर्धारित अवधि के भीतर निकाय में कोई भी दावे आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः इस उपनियमावली को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी :

उपनियमावली

1-**शीर्षक**—यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद की "प्रतिलिपि शुल्क" उपनियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2-**प्रकृति**—यह उपनियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद सीमा में प्रभावी होगी।

3-**परिभाषाएँ**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपनियमावली में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिकांसी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अधिकांसी अधिकारी से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अध्यक्ष से है।

(ङ) "नगरपालिका" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद से है।

(च) "नगरपालिका की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4—यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अभिलेख तथा लेखों की, जो नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के हों अथवा उनके कब्जे में हों कोई प्रतिलिपि अथवा कोई उद्धरण न ही दिया जायेगा और न ही ऐसे लेख या अभिलेखों का निरीक्षण करने की स्वीकृति ही प्रदान की जायेगी जब तक कि अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की लिखित अनुमति न प्राप्त हो जाय।

5—प्रतिलिपि दिये जाने का, निरीक्षण कराने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अधिशासी अधिकारी एवं उसके द्वारा नामित कर्मचारी में सुरक्षित है।

6—नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के सेवानिवृत्त/कार्यरत कर्मचारियों को उनके सम्बन्धित मामलों में निरीक्षण करने अथवा प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7—अधिशासी अधिकारी यदि कोई प्रतिलिपि देने, प्रमाण-पत्र देने अथवा निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र निरस्त कर देते हैं तो वह व्यक्ति बोर्ड/ जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अन्तिम होगा।

8—सिवाय उपर्युक्त के कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अभिलेखों अथवा लेखों का निरीक्षण करना या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना अथवा उसमें से कोई उद्धरण प्राप्त करना चाहता हो, तो अभिलेख अथवा लेख का स्पष्ट रूप से विवरण देते हुए अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र देना होगा, जिस पर रु0 2.00 का कोई स्टाम्प लगाना आवश्यक होगा।

9—बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद तथा राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के बीच किये गये किसी पत्र व्यवहार का अथवा किसी भी मामले का जिसे निरीक्षण करना जिसमें बोर्ड/ नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के हित में हानिकारक है, निरीक्षण करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसे अभिलेखों के उद्धरण की प्रतिलिपियां व प्रमाण-पत्र भी देने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

10—किसी ऐसे लेख के कोई उद्धरण नहीं किये जायेंगे जिन्हें पत्रावली से अलग करके पढ़ने पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये अन्तिम आदेशों से उल्टा अर्थ या आदेश निकलने की सम्भावना हो।

11—निरीक्षण शुल्क प्रार्थी द्वारा रु0 25.00 (रुपये पच्चीस) प्रति घण्टा या घण्टे के किसी भी भाग पर व्यय होगा। प्रथम घण्टे की निरीक्षण शुल्क की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ नत्थी कर दी जायेगी।

12—निरीक्षण के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, जिसका प्रारूप नीचे दिये गये शीर्षकों के अनुसार होगा :

1—क्रम संख्या।

2—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि तथा रसीद संख्या जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र की फीस प्राप्त हुई।

3—प्रार्थी का नाम व पता।

4—रजिस्टर या दस्तावेज जिसका निरीक्षण करना चाहा गया हो।

5—निरीक्षण प्रारम्भ करने का समय।

6—निरीक्षण समाप्त करने का समय।

7—पूरा समय जो निरीक्षण में लगा।

8—निर्धारित फीस।

9—रसीद संख्या, जिसके द्वारा फीस वसूल की गई।

13—सभी निरीक्षण अधिशासी अधिकारी/कार्यालय कर्मचारी की देख रेख में कराया जायेगा। उक्त कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि दस्तावेज या कागज को कोई क्षति न पहुँचे या उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। निरीक्षण की पूरी फीस वसूल कर लेने की भी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।

14—प्रार्थी स्वयं निरीक्षण कर सकता है या अपने किसी अन्य व्यक्ति से करा सकता है, परन्तु उस व्यक्ति जिससे निरीक्षण करवाना चाहता हो प्रमाण-पत्र में उसका नाम व पता का भी उल्लेख किया जायेगा, निरीक्षण करते समय उसकी प्रतिलिपि नहीं तैयार की जा सकती है।

15—प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना-पत्र करते ही अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित कोई नगर पालिका कर्मचारी उसकी प्रतिलिपियों के रजिस्टर में उल्लेख कर देगा, जिसका रजिस्टर निम्नलिखित शीर्षकों के प्रारूप में बनाया जायेगा।

1—क्रम संख्या।

2—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि तथा रसीद संख्या जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र की फीस प्राप्त हुई।

3—प्रार्थी का नाम व पता।

4—उस कागज का दस्तावेज का विवरण, जिसकी प्रतिलिपि व प्रमाण-पत्र चाहा गया।

5—प्रार्थना-पत्र जो किसी कमी को दूर करने की सूचनाओं की तिथि।

6-प्रतिलिपि शुल्क, जो वसूल किया गया तथा उसकी रसीद संख्या।

7-प्रतिलिपि तथा प्रमाण-पत्र में तैयार करने की तिथि।

8-प्रार्थी के हस्ताक्षर।

9-सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर।

10-अधिकांसी अधिकारी के हस्ताक्षर।

16-प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही उसकी भली भांति जांच कर ली जाय तो यथा समय तुरन्त प्रार्थी को सूचित कर दिया जायेगा अन्यथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दी जायेगी, कमी का विवरण दिया जायेगा। यदि सूचना देने या नोटिस लगाने के सात दिन के अन्दर कमी को दूर न किया तो प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

17-प्रतिलिपि तैयार होने पर उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि नोटिस लगाने के 15 दिन के अन्दर तैयार की गयी प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा न ले ली जाय तो वह नष्ट कर दी जायेगी और इस सम्बन्ध में दोबारा प्रार्थना-पत्र देना है तो निर्धारित सभी शुल्क उससे लिये जायेंगे।

18-प्रतिलिपि तैयार कर देने के पश्चात् कर्मचारी अपने तैयार करने के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर बनायेगा और अधिकांसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी उसका मिलान करके अपना हस्ताक्षर बनायेगा, तदोपरान्त सक्षम अधिकारी अपने हस्ताक्षरों से सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित करेंगे और नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद की सामान्य मोहर लगाई जायेगी।

19-निरीक्षण न कराने या प्रतिलिपि न देने के आदेश होने पर निरीक्षण या प्रतिलिपि शुल्क प्रार्थी को वापस कर दिया जायेगा। प्रार्थना-पत्र की फीस रु0 25.00 किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

20-आवश्यक प्रतिलिपि तीन दिन के अन्दर और साधारण प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र जमा होने के 7 दिन के अन्दर जारी कर दी जायेगी।

21-प्रतिलिपि शुल्क तथा प्रमाण-पत्र शुल्क प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होगा, जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करके रसीद उसी के साथ नत्थी कर दी जावेगी।

22-आवश्यक निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर, वाटर मार्क पेपर, जिस पर नकल दी जायेगी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ दिये जायेंगे :

क्रमांक	विवरण	साधारण (72 घण्टे के भीतर)	आवश्यक (24 घण्टे के भीतर)
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	जन्म-मृत्यु द्वितीय प्रतिलिपि शुल्क	50.00	100.00
2	जल संयोजन प्रतिलिपि शुल्क	100.00	200.00
3	अनुभव प्रमाण-पत्र	250.00	500.00
4	अदेय प्रमाण-पत्र	250.00	500.00
5	लाइसेन्स द्वितीय प्रतिलिपि शुल्क	250.00	500.00
6	भवन कर प्रतिलिपि शुल्क	100.00	200.00
7	अन्य शुल्क	150.00	250.00

23-इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में विहित प्राधिकारी/आयुक्त यदि संतुष्ट हैं कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरुपयोग नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार विहित प्राधिकारी/आयुक्त को होगा।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर नगर पालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। जो रु0 2,000.00 (रुपये दो हजार) तक किया जा सकता है।

यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। जिसके बारे में यह सिद्ध हो जायेगा कि अपराधी, अपराध करता रहा है। ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

रंजीता धामा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, लोनी,
गाजियाबाद।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, लोनी-गाजियाबाद

17 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1031/न0पा0परि0-लो0गा0/2021-22-संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 298(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर नगरपालिका परिषद्, लोनी अपनी सीमा में वाहन शुल्क उपविधि बनायी है। उपविधियों का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 300(1) के अधीन समस्त नगरवासियों से आपत्ति एवं सुझावों को आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" व "पंजाब केसरी" के अंक दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें नगरवासियों से दावे आपत्ति प्राप्त करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था। उक्त के क्रम निर्धारित अवधि के भीतर निकाय में कोई भी दावे, आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः इस उपनियमावली को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी :

उपनियमावली

1-**शीर्षक**—यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, लोनी, वाहन किराया शुल्क उपनियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2-**प्रकृति**—यह उपनियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका सीमा में प्रभावी होगी।

3-**परिभाषाएँ**—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपनियमावली में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अध्यक्ष से है।

(ङ) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद से है।

(च) "नगरपालिका की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4—यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, जो नगरपालिका के हों अथवा उनके कब्जे में हों किराये पर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की लिखित अनुमति न प्राप्त हो जाय।

5—वाहन किराये पर दिये जाने का, निरीक्षण कराने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के अधिशासी अधिकारी एवं उसके द्वारा नामित कर्मचारी में सुरक्षित होगा।

6—नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के सेवानिवृत्त/कार्यरत कर्मचारियों को उनके सम्बन्धित मामलों में किराये पर वाहन देने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7—अधिशासी अधिकारी, यदि कोई वाहन किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र निरस्त कर देते हैं तो वह व्यक्ति बोर्ड/जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और इस सम्बन्ध में बोर्ड/जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अन्तिम होगा।

8—यदि कोई भी व्यक्ति वाहन किराये पर लेना चाहता तो उसका विवरण देते हुये अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र देना होगा।

9—बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद तथा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के बीच किये गये किसी पत्र-व्यवहार का अथवा किसी भी मामले का, जिसमें बोर्ड/नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद के हित में हानिकारक है, वाहन किराये पर नहीं दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बोर्ड/नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम होगा।

10—वाहनों का किराया प्रति घण्टा, प्रति चक्कर व प्रति नग बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर लिया जायेगा।

11—किराये हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, जिसका प्रारूप नीचे दिये गये शीर्षकों के अनुसार होगा—

1—क्रम संख्या।

2—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि तथा रसीद संख्या, जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र की फीस प्राप्त हुई।

3—प्रार्थी का नाम व पता।

- 4—वाहन, जो किराये पर दिया गया।
- 5—वाहन किराये पर देने का समय।
- 6—वाहन किराये पर से आने का समय।
- 7—पूरा समय जो कार्य करने में लगा।
- 8—निर्धारित फीस (प्रति घंटा/प्रति नग)।
- 9—सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर।
- 10—अभ्युक्ति।

12—सभी वाहनों का किराया अधिशासी अधिकारी/किसी अन्य कर्मचारी की देख-रेख में वसूल किया जायेगा। उक्त कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी वाहन को कोई भी क्षति न पहुंचे या उसमें कोई परिवर्तन न हो। किराये की पूरी फीस वसूल करना सम्बन्धित कर्मचारी की पूरी जिम्मेदारी होगी।

13—किसी भी वाहन को नगरपालिका सीमा के बाहर भेजने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

14—यदि कोई भी व्यक्ति वाहन किराये पर चाहता है तो उसे प्रार्थना-पत्र के साथ अग्रिम जमानत धनराशि किराये के अनुसार जमा करना होगा, तत्पश्चात् प्रति घण्टा, चक्कर/प्रति नग के हिसाब से रसीद की प्राप्ति करा दी जायेगी।

15—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही उसकी भली भांति जांच कर ली जाय तो यथा समय तुरन्त प्रार्थी को सूचित कर दिया जायेगा अन्यथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दी जायेगी, कमी का विवरण दिया जायेगा। यदि सूचना देने या नोटिस लगाने के सात दिन के अन्दर कमी को दूर न किया तो प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

16—उपनियम की शर्तों में आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा व शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय जारी किये जा सकते हैं।

17—निरीक्षण न कराने या वाहन किराये पर न देने के आदेश होने पर प्रार्थी का शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

18—वाहन शुल्क प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होगा, जो प्रार्थना-पत्र जमा करके रसीद उसी के साथ नत्थी कर दी जायेगी :

क्रमांक	विवरण	किराया, प्रतिघण्टा/प्रतिनग/प्रति चक्कर
		रुपये
1	वाटर टैंकर	500.00
2	सीवर सेक्शन मशीन—	
	(i) प्रथम टैंक का मूल्य	1,000.00
	(ii) द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ टैंक आदि का मूल्य	800.00
3	बैकहो लोडर	800.00
4	मोबाइल टॉयलेट	1,000.00
5	पोकलेन मशीन	2,000.00
6	हाइड्रॉ मशीन	800.00
7	स्काई लिफ्ट	800.00
8	एनीमल कैचर	1,000.00
9	व्यक्तिगत मृत पशु को ले जाना	500.00

19—इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में विहित प्राधिकारी/आयुक्त यदि संतुष्ट हैं कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरुपयोग नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार विहित प्राधिकारी/आयुक्त को होगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (स0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 2,000.00 (रुपये दो हजार) तक हो सकेगा। यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 100.00 (एक सौ रुपये) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

रंजीता धामा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, लोनी,
गाजियाबाद।

सूचना

पहले मेरा नाम राम सुन्दरी था बाद में मेरा नाम राम सुन्दरी प्रजापति हो गया है। राम सुन्दरी और राम सुन्दरी प्रजापति दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरा ही नाम है अब भविष्य में मुझे राम सुन्दरी प्रजापति पुत्री स्व0 कतई, निवासिनी 21 चौखण्डी कीडगंज, प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना जाये।

राम सुन्दरी प्रजापति,
पुत्री स्व0 कतई,
नि0-21 चौखण्डी कीडगंज,
प्रयागराज।

NOTICE

I, W/o IC-24105H Lt. Col. Darshan Kumar Sharma (*Retd.*) R/o Flat No. 12 D, Hestia Apartments Plot no. 423, Vistaar Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U. P.-226010. Declare that my name Shankuntla Sharma in my Husband's army records is incorrect. My correct name is Shakuntla Sharma.

SHAKUNTALA SHARMA,
W/o Lt. Col. Darshan Kumar Sharma (*Retd.*)
Address-Flat No.-12D, Hestia Apartments,
Plot no. 423, Vistaar Khand,
Gomti Nagar Lucknow, U.P.-226010.

NOTICE

I, Jitendra Kumar Yadav S/o Surendra Prasad Yadav, R/o H. No. 112 Guru Nanak Nagar, District Sitapur, U.P. 261001 have changed the name of my minor son Reyan Krishna, aged 6 years and he shall hereafter be know as Vaibhav Krishna.

Jitendra Kumar Yadav.

NOTICE

I, Jitendra Kumar Yadav S/o Surendra Prasad Yadav, R/o H.No. 112, Guru Nanak Nagar, Distt. Sitapur, U.P. 261001 have changed the name of my minor daughter Vaibhavi Yadav aged 13 years and she shall hereafter be know as Vaibhavi Krishna.

Jitendra Kumar Yadav.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म आदर्श सिक्योरिटी सर्विसेज रजि0 नं0 ए0एल0 4624,

दिनांक 02 जुलाई, 2014 को निबंधक फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स इलाहाबाद के यहां पर रजिस्टर्ड है। दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को उपरोक्त फर्म से संदीप पाण्डेय स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं। अब इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है। तदुपरान्त निर्मल चन्द्र पाण्डेय इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है भविष्य में अब इस फर्म का संचालन अरुणा पाण्डेय एवं निर्मल चन्द्र पाण्डेय करेंगे।

निर्मल चन्द्र पाण्डेय,
पार्टनर,
आदर्श सिक्योरिटी सर्विसेज,
रामपुर करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "ए0वाई0 इलेक्ट्रिकल्स", पता मोहल्ला सतुने संग मस्जिद चाह खजान खान, तहसील सदर, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को श्री मो0 यूसुफ पुत्र नबी अहमद, निवासी म0नं0 103, ग्राम इन्द्रा, तहसील सदर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को श्री नाजिम अली पुत्र श्री खलील अहमद, निवासी पीपली गांव, पो0 केमरी, जिला रामपुर, हाल निवासी मोहल्ला मस्जिद चाह खजान खान, तहसील सदर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री आमिल मोहसिन व श्री नाजिम अली रह गये हैं।

आमिल मोहसिन,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "ए0वाई0 इलेक्ट्रिकल्स",
पता-मोहल्ला सतुने संग मस्जिद चाह,
खजान खान, तहसील सदर,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्वराज रबर प्रोडक्ट्स, गली नं0 09, पंजाब एक्सपेलर कम्पाउण्ड, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद-201002, उ0प्र0 पंजीकरण संख्या GHA/0007482 के साझीदार 1-स्व0 सुरेन्द्र कुमार मित्तल का स्वर्गवास दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 में हो जाने के कारण फर्म साझीदारों द्वारा आपसी सहमती से फर्म साझेदारी दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा फर्म साझीदारी में अन्य परिवर्तन न करते हुये शेष साझीदार श्रीमती जीवन लता व

श्री विपिन मित्तल द्वारा फर्म साझेदारी को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान साझीदार 1—श्रीमती जीवन लता, 2—श्री विपिन मित्तल है।

विपिन मित्तल,
मेसर्स स्वराज रबर प्रोडक्ट्स,
गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन, शॉप नं0 41, एक्सप्रेस मॉर्किट, नीति खण्ड-III, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ0प्र0-201014, पंजीकरण संख्या GHA/0003494 की सप्लीमेंटरी पार्टनरीशिप डीड दिनांक 28 जून, 2021 के अनुसार साझीदार—श्री सौरभ साहनी अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं व फर्म का पता सर्वसम्मति से परिवर्तित कर 5/1311, मोहन मिकिन सोसाइटी, सेक्टर-5, वसुंधरा गाजियाबाद किया गया है। फर्म में वर्तमान साझीदार 1—अमित त्यागी, 2—ओमप्रकाश त्यागी, 3—हीना त्यागी हैं।

अमित त्यागी,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स काशीनाथ दुर्गा प्रसाद, न्यू मीना बाजार रामकोला, जिला कुशीनगर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 13 फरवरी, 2020 से श्री दुर्गा प्रसाद तुलस्यान व श्री दिलीप कुमार तुलस्यान एवं श्री कन्हैया लाल तुलस्यान जी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण सं0 KUS/0006463 पर पंजीकृत है। यह की साझेदार श्री दुर्गाप्रसाद तुलस्यान जी की मृत्यु दिनांक 09 जुलाई, 2021 को हो गयी है एवं साझेदार डीड दिनांक 09 जुलाई, 2021 से श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व0 दुर्गा प्रसाद तुलस्यान साझेदार के रूप में शामिल हो गयी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

दिलीप कुमार तुलस्यान,
साझेदार,
मेसर्स काशीनाथ दुर्गाप्रसाद, कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सर्वश्री प्रभूदास अडवानी, चुन्नी लाल अडवानी दोनों निवासीगण 122/328, शास्त्री नगर, कानपुर, हासानन्द अडवानी एवं दीपक कुमार अडवानी दोनों निवासीगण 122/721, शास्त्री नगर, कानपुर सप्लीमेंटरी (अनुपूरक) एवं रेक्टिफिकेशन (संशोधित) डीड दिनांक 01 जनवरी, 2018 एवं 10 जून, 2019 के अनुसार फर्म में एस0टी0 अडवानी एण्ड क0, पंजीकृत पता 122/721, एकता भवन, शास्त्री नगर, कानपुर नगर में भागीदार हैं।

हासानन्द अडवानी,
पार्टनर,
मे0 एस0टी0 अडवानी एण्ड क0 कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एन0पी0एस0 इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट्स, प्लॉट नं0 जे-14, साईट-सी, सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201306 की साझीदारी में श्री श्यामवीर सिंह एवं श्री जयनेन्द्र सिंह साझीदार थे। फर्म की साझीदारी में दिनांक 28 मई, 2021 को श्रीमती निधि रानी सम्मिलित हुई हैं तथा श्री श्यामवीर सिंह दिनांक 28 मई, 2021 को स्वर्गवास होने के कारण फर्म की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार वर्तमान में श्री जयनेन्द्र सिंह एवं श्रीमती निधि रानी साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जयनेन्द्र सिंह,
साझीदार,
मेसर्स एन0पी0एस0 इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट्स,
प्लॉट नं0 जे-14, साईट-सी, सूरजपुर
इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201306।